रांची, सोमवार, 20.05.2019

लोकतंत्र का महापर्व

अंतिम चरण के मतदान के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा पूरा हुआ है और अब नतीजों का इंतजार है. हमारा देश उन गिने-चुने देशों में है, जहां औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद से सार्वभौम मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित गणतांत्रिक व्यवस्था चली आ रही है. भारत में पंजीकृत मतदाताओं की मौजूदा संख्या लगभग 90 करोड़ है, जिनमें से अधिकतर ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया है. छिटपुट हिंसा और गड़बड़ियों को छोड़ दें, तो सात चरणों की यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है. निश्चित रूप से चुनाव आयोग, सुरक्षाबलों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए यह संतोष का विषय है. एक ओर जहां इस चुनाव की सफलता गौरव का विषय है, वहीं इसके अनुभवों से सीख लेते हुए हमें इसे उत्तरोत्तर कारगर और मजबूत बनाने की कवायद पर भी ध्यान देना चाहिए. प्रचार अभियान और मतदान में महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक स्वागतयोग्य पहलू है, परंतु उम्मीदवारी में इनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के बारे में विभिन्न दलों को विचार करना चाहिए.

प्रचार के दौरान नेताओं ने भाषायी और व्यावहारिक मर्यादाएं लांघी. देश को नेतृत्व देनेवाले व्यक्तियों और पार्टियों को ऐसे बर्ताव से बाज आना चाहिए.

आबादी के लिहाज से इन दोनों की तादाद बहुत बड़ी है. हमारी राजनीति धनबल और बाहुबल के ग्रहण से लंबे समय से ग्रस्त रही है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कमी भी आ रही है, किंतु प्रचार के दौरान बेतहाशा खर्च और मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसा, सामान व शराब बांटने की शिकायतें चिंताजनक है. गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे उम्मीदवारों का चुनावी मैदान में होना भी एक बड़ा सवाल है. पार्टियों और प्रत्याशियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तथा परस्पर टीका-टिप्पणी चुनाव का जरूरी आयाम है. इससे उम्मीदवारों के बारे में समझ बनाने में मतदाताओं को बड़ी मदद मिलती है. प्रचार के दौरान ऐसे कई मौके आये, जब बहस में नेताओं ने भाषायी और व्यावहारिक मर्यादा को लांघते हुए बयानबाजी की. देश को नेतृत्व देनेवाले व्यक्तियों और पार्टियों को ऐसे बर्ताव से बाज आना चाहिए. पारदर्शिता और प्रशासनिक निष्पक्षता के बिना चुनाव जैसी लोकतांत्रिक कार्यवाही को समुचित ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता है. निर्वाचन आयोग, अधिकारियों तथा राजनीतिक दलों को आपसी समझ-बूझ से ऐसे नियम और निर्देश तय करने चाहिए, जहां पक्षपात का प्रश्न ही पैदा न हो सके. ध्यान रहे, हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब और निम्न आय वर्ग से है. मतदान में इसकी भागीदारी भी बढ़ चढ़कर होती है. ऐसे में मतदाता सूची में इस तबके के लोगों के नाम शामिल करने से लेकर उन्हें मर्जी से मतदान करने तक की सुविधा मुहैया कराना बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था कि लोकतंत्र में आम चुनाव एक पवित्र कर्मकांड के समान है. हर मत दूसरे मतदाता को प्रोत्साहित करता है और हर मत लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाता है. महामहिम के इस विचार को आदर्श मानते हुए हमें चुनावी प्रक्रिया को लगातार बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए.

सीमित चरणों में हों आम चुनाव

आशुतोष चतुर्वेदी
प्रधान संपादक, प्रभात खबर
ashutosh.chaturvedi@prabhatkhabar.in

चुनाव किसी भी लोकतंत्र के आधार स्तंभ होते हैं. हर आम चुनाव लोकतंत्र को समृद्ध कर जाता है. सदियों तक सत्ता परिवर्तन हमेशा रक्तरंजित रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सत्ता परिवर्तन को सहज कर दिया है. लोकसभा चुनाव वास्तव में लोकतंत्र का महाकुंभ है. इतनी व्यापकता, इतनी विविधता की मिसाल दुनियाभर में कहीं नहीं है. यदि चुनावों की व्यापकता पर नजर डालें, तो 17वीं लोकसभा के लिए 90 करोड़ लोग मतदान के योग्य थे और इनमें से लगभग 60 फीसदी लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया. महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 से 19 साल के डेढ़ करोड़ मतदाताओं ने इस चुनाव में पहली बार हिस्सा लिया और लगभग आठ करोड़ 43 लाख नये मतदाताओं ने इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. सात चरणों में हुए मतदान में 10 लाख पोलिंग बूथ पर वोट डाले गये. लोकसभा के लिए मतदान सकुशल संपन्न हो गया और अब बस नतीजों का इंतजार है. नतीजे किस करवट बैठेंगे, इसको लेकर नेताओं और पार्टी समर्थकों की धड़कनें तेज हैं. चुनाव सात चरणों में और लगभग छह सप्ताह चला और यह सभी के लिए थकाऊ साबित हुआ. पिछले दो महीने से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की गतिविधियां ठप पड़ी हैं. पूरी मशीनरी चुनाव संपन्न कराने में व्यस्त है. नेता, मंत्री और संत्री सब चुनाव में जुटे हुए हैं. रही सही कसर चुनाव आचार संहिता ने पूरी कर दी. यह सही है कि निष्पक्ष चुनाव जरूरी है, लेकिन आचार संहिता के कारण पिछले दो महीने से सरकारी निर्णय अटके पड़े हैं. हमें इस पर विचार करना होगा कि कैसे चुनाव को सीमित समय में कराया जा सके, क्योंकि इस दौरान देश लगभग स्वतः संचालित अवस्था में होता है. हर पार्टी के लिए आम चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है और पार्टियां पूरी ताकत झोंककर उसे जीतने की कोशिश करती हैं. यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी अस्त्रागार में से किसी अस्त्र को दागने से नहीं चूकते हैं. इस बार अंतिम दौर तक आते-आते बात मुद्दों तक नहीं रह गयी और नेताओं की बयानबाजी राजनीतिक मर्यादा को तार-तार कर गयी. चुनावों के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा को ठेस पहुंचायी है. जाने माने समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा जाना शर्मनाक है. साथ ही महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के पक्ष में प्रज्ञा ठाकुर का बयान मर्यादा की सभी हदों को पार कर गया. मेरा मानना है कि चुनाव की इतनी लंबी प्रक्रिया ठीक नहीं है. लंबे चुनाव के संचालन की अपनी अलग चुनौतियां हैं. चुनावों के दौरान जो घटनाएं घटित हुईं, जिनको लेकर बार-बार आयोग सवालों के घेरे में रहा. एक तरह से चुनाव आयोग का भी यह कड़ा इम्तिहान था. उसकी साख पर भी बार-बार सवाल उठाये गये. मेरा मानना है कि अगर चुनाव पांच चरणों में ही संपन्न होते तो शायद बेहतर होता.

यह सही है कि हरेक आम चुनाव राजनीति का एक नया संदेश देकर जाता है. पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विकास के उनके वादे पर लोगों ने वोट किया था. लेकिन, इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा आम चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया. यह सच्चाई है कि अब चुनाव जमीनी मुद्दों पर नहीं लड़े जाते. चुनावों में किसानों की समस्याएं, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की स्थिति जैसे विषय प्रमुख मुद्दे नहीं बनते. इस बार के चुनाव पर नजर डालें तो पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित था या तो आप उनके साथ हैं, उनके समर्थक हैं अथवा आपका उनके धूर विरोधी हैं. कई स्थानों पर यह ध्रुवीकरण बहुत गहरा था. कई स्थानों पर ऐसा देखने में आया कि लोगों ने भाजपा उम्मीदवार को नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी को वोट दिया. चुनाव संसदीय प्रणाली की बजाए राष्ट्रपति प्रणाली जैसे ज्यादा नजर आया. जैसे दो उम्मीदवार ही मैदान में थे- एक नरेंद्र मोदी तो दूसरे राहुल गांधी. हालांकि, कई राज्यों में गठबंधन के नेताओं का दबदबा साफ नजर आया. चुनाव में इस बार कई अन्य दिलचस्प बातें देखने को आयीं. कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों से दूरी बनाते हुए नरम हिंदुत्व की राह पकड़ी और दोनों भाई बहन- राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिरों में मत्था टेकते नजर आये, जबकि यह भाजपा का कार्यक्षेत्र रहा है. इसके पहले भाजपा कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों की तरफदारी करने का आरोप लगाती रही है. लेकिन, कांग्रेस ने इस बार उनसे दूरी बनाये रखी. सोशल मीडिया में भाजपा का पलड़ा हमेशा भारी रहता आया है, पर इस बार ऐसा नहीं था. कांग्रेस भी सोशल मीडिया में सक्रिय थी. कांग्रेस ने राफेल, किसानों की नाराजगी, जीएसटी और नोटबंदी के मुद्दे उठाये, वहीं भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अलावा अपने मजबूत संगठन के जरिये बूथ लेवल पर काम किया. सघन प्रचार और ध्रुवीकरण भाजपा का मजबूत पक्ष रहा. 2014 के लोकसभा चुनावों में हिंदी पट्टी के राज्यों यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड का केंद्र में भाजपा की सरकार बनवाने में बड़ा योगदान रहा है. चुनाव परिणामों से साफ होगा कि हिंदी पट्टी के ये गढ़ क्या अब भी भाजपा के साथ हैं अथवा महागठबंधन ने इनमें सेंध लगा ली है.

पश्चिम बंगाल की हिंसा ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ठेस पहुंचायी. प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा जाना शर्मनाक है. महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के पक्ष में प्रज्ञा ठाकुर का बयान तो मर्यादा की सभी हदों को पार कर गया.

इस चुनाव में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार रही. यह भेद कर पाना बेहद कठिन था कि कौन सी खबर सच है और कौन सी खबर फर्जी है. व्हाट्सएप के दौर में सुबह से शाम तक खबरों का आदान-प्रदान होता है और पता ही नहीं चलता कि कितनी तेजी से फेक न्यूज के आप शिकार हो गये. एक ओर तो दुनिया कंप्यूटर और इंटरनेट के दौर से आगे निकल चुकी है. माना जा रहा है कि यह सदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है. अब बात इंटरनेट से मतदान की चल रही है. ऐसे में हमारे कुछेक राजनेता हमें पुराने दौर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. अब तो यह दस्तूर हो गया है कि हर चुनाव के पहले इवीएम पर सवाल उठाये जाते हैं. लेकिन, लोकतंत्र का बुनियादी तत्व है कि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष हो. मतदाता को यह भरोसा हो कि उसका वोट वहीं पड़ा है, जहां वह देना चाहता था. इतनी बड़ी चुनाव प्रक्रिया में कुछेक इवीएम में तकनीकी खराबी आ सकती है और उसे तत्काल बदला जाता है. लेकिन हर बार उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाये जाने से लोगों के मन में संशय होता है. विपक्षी दल इवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गये, लेकिन वहां भी उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया. अनेक विपक्षी दल चाहते हैं कि मत पत्रों की पुरानी व्यवस्था को वापस लाया जाए. यह तथ्य भी सबके सामने है जब मत पत्रों का इस्तेमाल होता था तो सही स्थान मुहर न लगने के कारण लगभग 4 से 5 फीसदी वोट रद्द हो जाते थे. दूसरे यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में बूथ कैप्चरिंग बड़ी समस्या थी. कुछ समय पहले राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें इसी इवीएम के माध्यम से हुए मतदान से ही बनीं. यह दलील कैसे चलेगी कि जब आप जीतें तो ठीक अन्यथा मशीन खराब है.

बोधि वृक्ष

गुरु सेवा

अपने आश्रम में संन्यासियों को गुरु अपने साथ रहने की अनुमति देते हैं. गुरु एक संन्यासी के अहंकार के मुखौटे को उसके पास ही छोड़ देते हैं, ताकि वह उसके साथ भी विभिन्न परिस्थितियों का सामना कर सके. लेकिन, गुरु परोक्ष रूप से अंततः उसे उसके अहंकार से मुक्त करने के लिए तैयार करते रहते हैं. संन्यासी के कर्मों के क्षय के लिए गुरु अपना खेल खेलते हैं, जिसे 'गुरु माया' कहते हैं. वे संन्यासी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझते हैं और कर्मों का क्षय करने के लिए उसे विभिन्न गतिविधियों में संलग्न कर देते हैं. गुरु उसे किसी प्रकार के कर्मयोग में लगा देते हैं, जैसे, रसोईघर, बागवानी, छापाखाना या आश्रम की सफाई. इस तरह के कर्मयोग में भिन्न प्रकार की सजगता की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग आत्म-विश्लेषण के लिए किया जा सकता है. गुरु संन्यासी को कर्मयोग के क्रम में मौन रहने का निर्देश भी दे सकते हैं. संन्यासी के अंदर गहराई में दबे संस्कारों को सतह पर लाने का यह एक प्रभावकारी उपाय है, जिसके द्वारा उसे अपने कर्मों का क्षय करने में मदद मिलती है. इस प्रकार संन्यासी को विभिन्न प्रकार के कार्य देकर गुरु यह समझ जाते हैं कि स्वाभाविक रूप से कौन-से कार्य के द्वारा वह अपने कर्मों का क्षय कर पायेगा. संन्यासी अपनी सुप्त प्रवृत्तियों को एक योग शिक्षक, लेखक, गायक, शोधकर्ता, माली, रसोइया, प्रबंधक या सचिव जैसी भूमिकाओं में प्रकट कर सकता है. इस प्रकार संन्यासी जब गुरु की सेवा करता है, तो बिना नये कर्मों का संचय हुए, पुराने कर्मों का क्षय होता जाता है. दैनिक कामकाज के माध्यम से अपने सुप्त संस्कारों को प्रकट कर संन्यासी उच्चतर साधना के लिए आधार तैयार कर लेता है. गुरु सेवा द्वारा जैसे-जैसे संन्यासी के कर्मों का क्षय होता है, वह अधिक शांति और वैराग्य पाता है. जब मन एकाग्र एवं स्थिर हो जाता है, तब वह अधिक गहराई से अधिक देर तक ध्यान कर सकता है. संन्यासी का मन एक स्वच्छ दर्पण की तरह हो जाता है, जिसमें गुरु की शिक्षा प्रतिबिंबित होने लगती है.

स्वामी निरंजनानंद सरस्वती

विद्यासागर और महात्मा गांधी

रविभूषण
वरिष्ठ साहित्यकार
ravibhushan1408@gmail.com

ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मूर्तिभंजक उन मूल्यों के विरुद्ध हैं, जिनके प्रति विद्यासागर समर्पित थे. देश की वर्तमान राजनीति को न तो विद्यासागर से मतलब है, न गांधी से.

चार महीने बाद महान शिक्षाविद, समाज सुधारक, दार्शनिक, लोकोपकारक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी, मानवतावादी, दानवीर, लेखक, अनुवादक, एकेडमिक, नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक राजा राममोहन राय (22 मई, 1772- 27 सितंबर, 1833) के उत्तराधिकारी बंगाल नवजागरण के प्रमुख स्तंभ ईश्वरचंद्र विद्यासागर (26 सितंबर, 1820- 29 जुलाई, 1891) की द्विजन्मशती आरंभ हो रही है और अभी महात्मा गांधी (2 अक्तूबर, 1869- 30 जनवरी, 1948) की 150वीं जयंती मनायी जा रही है.

लगभग एक ही समय चुनाव-प्रचार के दौरान कोलकाता में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गयी और मालेगांव बम विस्फोटक की मुख्य आरोपी, भोपाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे (19 मई, 1910- 15 नवंबर,1949) को देशभक्त कहा- 'नाथुराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे.' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की- 'साध्वी प्रज्ञा को कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा.' बाद में प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांगी. हेमंत करकरे पर दिये अपने बयान के बाद भी उन्होंने माफी मांग ली थी. प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे-संबंधी विचार को भाजपा ने उनका निजी विचार कहा और जनता को यह बताया कि पार्टी उनके साथ नहीं है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दस दिन में अनुशासनात्मक कमेटी द्वारा फैसला लेने की बात कही है. जबकि मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को 'नीच' कहे जाने पर पार्टी से निलंबित कर दिया था. भाजपा ने प्रज्ञा ठाकुर को निलंबित क्यों नहीं किया? प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने की बात विचारधारा और राष्ट्रहित के खातिर कही गयी है.

ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति किसने तोड़ी? उन्मादी भीड़ तो तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों की थी. बिना किसी ठोस प्रमाण के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने यह मूर्ति तोड़ी. बंगाल में चुनावी हिंसा साठ के दशक के अंत से आरंभ हुई है. बंगाल का भद्र समाज ही नहीं, सामान्य जन भी अपने नायकों-महानायकों के गौरव को कभी नहीं भूलता. ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्तिभंजक वह समाज शायद ही हो सकता है. अहंकारियों, उन्मादियों, उपद्रवियों, विद्याहीनों, समाज संहारकों की बात अलग है. विद्यासागर ने सच्चे नागरिक का धर्म स्वहित से पहले समाजहित और देशहित को माना था. उन्होंने संयम के साथ विद्यार्जन को महत्व दिया था और विद्या का संबंध सबके परोपकार से जोड़ा था. संयम से विवेक को, ध्यान को एकाग्रता से जोड़कर शांति, संतुष्टि और परोपकार को मनुष्यता से संबंध-स्थापन किया था. 'विद्या' को उन्होंने 'सबसे अनमोल धन' कहा है. उन्हें 'विद्यासागर' की उपाधि उनके कॉलेज ने प्रदान की. बाद में वे 'दयार सागर' भी कहलाये. माइकल मधुसूदन दत्त ने उनमें प्राचीन ऋषियों की-सी प्रतिभा और प्रज्ञा, अंग्रेजों की-सी ऊर्जा और बंग-माता की-सी सहृदयता देखी थी. गांधी ने उन्हें 1905 में केवल 'विद्या का सागर' न मानकर 'करुणा और उदारता आदि अनेक गुणों के सागर' भी कहा और रबींद्रनाथ ठाकुर ने उनका चारित्रिक गौरव केवल उनकी करुण और विद्या में न देखकर 'उनके निर्भ्रांत मानवीय गुणों एवं उनके अटल साहस' में भी देखा.

विद्यासागर भुवनेश्वर विद्यालंकार के प्रपौत्र, रामजय तर्कभूषण के पौत्र और ठाकुर दास बंद्योपाध्याय के पुत्र थे. नाना तर्कशास्त्री रामकांत तर्कवागीश थे. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यासागर ने क्रांतिकारी कार्य किये. साल 1856 में उनके प्रयत्नों से ही 'विधवा पुनर्विवाह कानून' बना. बंगाली शिक्षा और संस्कृति के विकास में उनका अप्रतिम योगदान है. बालविवाह, बहुविवाह, सतीप्रथा के वे विरोधी थे. उनके एकमात्र पुत्र नारायण चंद्र वंद्योपाध्याय ने स्वेच्छा से भावसुंदरी से विधवा-विवाह किया. शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए प्रत्येक जिले में मॉडल स्कूल खोलने की विद्यासागर ने योजना बनायी और योग्य अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल खोले. उनके महत्व को समझने के लिए सुबत्र चंद्र मिश्रा की 675 पृष्ठों की, 36 अध्यायों में लिखी गयी पुस्तक 'ईश्वरचंद्र विद्यासागर एंड हिज इल्यूसिव माइलस्टोंस' (न्यू बंगाल प्रेस, 1902) विशेष महत्वपूर्ण है. विद्यासागर के निधन के बाद उनके स्त्री प्रशंसकों ने 'लेडीज विद्यासागर कमेटी' की स्थापना की. शांतिपुर के जुलाहों ने साड़ियों की किनारी पर विधवा पुनर्विवाह की प्रशंसा वाले पद्य को शामिल किया था, जो विद्यासागर साड़ियां कहलायीं.

ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मूर्तिभंजक उन मूल्यों के विरुद्ध हैं, जिनके प्रति विद्यासागर समर्पित थे. पिछले कुछ वर्षों में देश के प्रमुख शिक्षा संस्थानों और विद्यानुरागियों पर हमले किसने किये? महात्मा गांधी अखंडता और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं. इसलिए गोडसे को देशभक्त कहनेवालों की मानसिकता हमें समझनी होंगी. हाल में 'टाइम' पत्रिका में आतिश तासीर ने नरेंद्र मोदी को 'डिवाइडर इन चीफ' कहा है. देश की वर्तमान राजनीति को न तो विद्यासागर से मतलब है, न गांधी से. गांधी शांति, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे. भाजपा और उनके अनुयायी-समर्थक क्या सचमुच शांति, सत्य और अहिंसा के साथ हैं? फिर हमारे चारों ओर अशांति, झूठ और हिंसा क्यों है? प्रश्न बंगाली अस्मिता का ही नहीं, भारतीय अस्मिता की रक्षा का भी है. गांधी ने पूरे देश को एक किया. आज विभाजनकारी शक्तियां प्रबल हैं. सत्तालोलुपों ने देश को नरक-द्वार पर ला खड़ा कर दिया है.

आपके पत्र

अनमोल धरोहरों पर हमला!

बंगाल में चुनावी हिंसा के बीच एक शिक्षण संस्थान का रणक्षेत्र में तब्दील होना बेहद चिंताजनक है. सवाल यह नहीं है कि मूर्ति किसने तोड़ी, सवाल यह है कि राजनीति इस देश को कहां ले जा कर छोड़ेगी. चुनाव के दौरान हिंसा के लिए मशहूर बंगाल आज भी अपने कलंक से उबर नहीं पाया है. ईश्वरचंद विद्यासागर जितने महत्वपूर्ण देश के लिए थे, उतने शायद अकेला बंगप्रदेश के लिए भी थे. ऐसे में यह बात कल्पना के परे लगती है कि बंगाल के लोगों ने विद्यासागर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है. वे पत्थर चाहे अंदर के थे या बाहर के, मगर निश्चित रूप से राजनीतिक थे. देश की अनमोल धरोहरों पर हमला हमारी भावी राजनीति का चरित्र और चेहरा साफ उजागर करता है. भले ही ऐसे हमलों से किसी को सियासी लाभ मिले, मगर लोकतंत्र के बहते लहू को रोक पाना मुमकिन नहीं होगा. बेशक सत्ता की खींच-तान हो, मगर महापुरुषों की मूर्तियों पर की जाने वाली राजनीति देश को गर्त में न ले जाये.

एमके मिश्रा, रातू, रांची

मोदी के केदारनाथ दर्शन पर दोहरा रवैया क्यों

जिन लोगों को हिंदू नेताओं का जालीदार टोपी और हरे कुर्ते, दुपट्टे लगाकर इफ्तार में जाना ढोंग या नाटक न लगा, उन्हें मोदी का गेरुआ पहन कर साधना करना बुरा लग रहा है. अपनी इसी मूर्खता और विभाजन के कारण हिंदू समाज की न कोई इज्जत करता है, न उसके मत का या किसी मांग का आदर करता है. यह भी पहली बार देखा कि इस बार किसी राष्ट्रीय दल के नेता ने जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी की तस्वीरें जारी नहीं करवायी. वाकई अफसोस होता है ऐसे दोहरे रवैये पर. नियमित वेस्टर्न कपड़े पहनने वाले इन दिनों तरह-तरह के वस्त्र, जनेऊ और धोती साड़ी पहनने का ड्रामा कर रहे हैं, उन पर कुछ नहीं कहते. जबकि मोदी का हिंदुत्व रुझान और उनकी आस्था कोई नयी बात नहीं है. वे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद पशुपतिनाथ भी गये थे और पिछले साल भी केदारनाथ बद्रीनाथ गये थे.

शिखर चंद जैन, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता

परिणाम की प्रतीक्षा!

2019 के इस इस बेहद हंगामेदार और लंबे लोकसभा चुनाव के परिणाम का अब जनता को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है. सभी के अलग-अलग अंदाज हैं. भाजपा नेता तीन सौ का आंकड़ा पार करने की पूरी आशा लगाये हुए हैं. वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां और नेता तो अब मोदी को सत्ता से बाहर ही देख रहे हैं. कुछ लोगों को यह भी अंदाज है कि बहुमत किसी भी पार्टी को न मिले और मिलीजुली ही सरकार बन पाये. एक यह भी अंदाज है कि मत विभाजन का लाभ भाजपा को मिलेगा और अभी वही सत्ता में रहेगी भले ही पहले से उसकी सीटें कुछ कम हों. बड़ी अजीब और दुर्भाग्य की बात है कि बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी और सुनियोजित विकास पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है. हर बार वही ढाक के तीन पात ही दिखाई देते हैं.

वेद मामूरपुर, नरेला

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है

कुछ अलग

महानता के सीजन

आलोक पुराणिक
वरिष्ठ व्यंग्यकार
puranika@gmail.com

एक राज्य सरकार ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में महाराणा प्रताप की महानता कम कर दी है, अकबर की बढ़ा दी है. वीर सावरकर के बारे में बताया गया है कि उन्हें सावरकर माना जा सकता है, पर वीर नहीं. ऊपर कहीं ये महान आत्माएं बात करती होंगी, तो कुछ यूं वार्तालाप होता होगा-

हां भई सावरकरजी, अब कहां-कहां महान हो?

देखिये उन राज्यों में महान ना बचे. पर कुछ नये राज्यों में शायद महान घोषित हो जायें.

हां, भई वक्त बहुत पेचीदा हो गया है. महाराणा प्रताप भी अब कुछ कम महान रह गये हैं. हां उस राज्य में ढुढुमल खोपटिया नये महान हो गये हैं. सुना है कि खोपटियाजी के वंशजों ने बहुत भारी रकम चंदे में उस राजनीतिक दल को दी है, तो खोपटिया महान घोषित हो गये हैं. खोपटिया के वंशजों के पास बहुत पैसा है देने के लिए, तो वह महान हो लिए.

नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर तो महाराणा प्रताप महान थे. वैसे महाराणा प्रताप में यह क्षमता तो अब भी है कि वे वोट दिलवा सकें. इसलिए उन्हें सिलेबस से ना हटाया जा सकता, हां उनकी महानता कम की जा सकती है.

तो क्या भविष्य में इस तरह के चुनावी वादे संभव हैं कि अगर हमारी सरकार आयी, तो हम चुन्नुमल खोपटिया को सौ पॉइंट का महान घोषित कर देंगे, बाकी सबको बाहर कर देंगे सिलेबस से? महानता के पॉइंट घोषित होंगे- सौ पॉइंट के महान, पचास पॉइंट के जूनियर टाइप के महान.

महानता पर गर्व नहीं करना चाहिए, सब कुछ अस्थायी है. आज महाराणा महान हैं, कल खोपटियाजी महान होंगे. फिर कोई सरकार आकर महापुरुष विनिवेश मंत्रालय खोल सकती है. जो पुराने महापुरुषों का विनिवेश कर देगा. पुराने महापुरुष कबाड़ के भाव निकाल दिये जायें, नये खोपट, पोपट भर्ती किये जायें.

महानता के सीजन हैं, कोई कभी महान है, कोई कभी महान है. सार्वकालिक महानता के दौर गये. नेहरूजी ऊपर से देखते होंगे कि हाय नीचे क्या-क्या मेरे नाम में लगाया जा रहा है. गांधी उन्हें तसल्ली देते होंगे- चिंता ना करें, सैकड़ों भ्रष्ट नेता, महाभ्रष्ट संस्थान मेरे नाम पर चल रहे हैं, सब कमा खा रहे हैं, मैं कुछ ना कर सकता. आप भी शांत होकर बैठिये.

महानता शेयर बाजार के भावों की तरह हो गयी है- कुछ वक्त बाद महानता की रिपोर्ट बाजार रिपोर्ट की तर्ज पर आने लगे कुछ इस तरह से- आज उस पार्टी के चुनाव जीतने के बाद चुन्नूमल खोपटिया की महानता के भाव ऊंचे बोले गये. महात्मा गांधी की महानता के भावों में कुछ नरमी देखी गयी. महात्मा गांधी के नाम पर चलनेवाले करीब पांच हजार संस्थानों में इतने हजार में निकम्मेपन और भ्रष्टाचार की जांच चल रही है. नये उभरते महानों में खटियामल जोड़ू के भाव बढ़ने की उम्मीद है, आप जोड़-तोड़ गठबंधन के उस्ताद हैं.

खैर, अब तो महानता पर गर्व करने के दिन गये. बिग बॉस की तरह महानता के भी सीजन आने लगे हैं!

देश दुनिया से

सूखे की चपेट में आ गया है उत्तर कोरिया

उत्तर कोरिया सदी के सबसे भयानक सूखे का सामना कर रहा है. यह खबर उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने दी है. कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने देश की स्थिति पर गहरी चिंता जतायी थी. दुनिया से अलग-थलग देश उत्तर कोरिया पर उसके परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के कारण कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं. इन सब के बीच यह देश अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि यहां खाने की कमी का इतिहास पुराना है. चार दशक पहले भी वहां ऐसी स्थिति थी, जब बारिश कम होने से भोजन का संकट पैदा हो गया था. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले साल यहां जो पैदावार हुई, वह पिछले एक दशक में सबसे कम थी. अनुमान है कि कम-से-कम पांच लाख टन कम पैदावार हुई. जेएनयू के प्रो संदीप मिश्रा के मुताबिक, उत्तर कोरिया को अपनी पूरी आबादी के लिए करीब 50 लाख टन पैदावार की जरूरत होती है, लेकिन पिछले एक दशक से इसमें लगभग हर साल 5-6 लाख टन की कमी हो रही है. उत्तर कोरिया इसकी भरपाई संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अलावा अंतरराष्ट्रीय मदद के जरिये करता है. उसके पास दूसरे देशों से सप्लाई कम होती जा रही है और खाना खरीदने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भी पर्याप्त नहीं है.

कार्टून कोना

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम